School of Economics

Sub. - Indian Economy

Class - M.A. (IVth) sem. CBCS

Teacher - Dr. Dharmendra Singh

~~Unit 2~~ Topic - Banking system in india
(भारत में बैंकिंग)

(V) भारत में बैंकिंग
(BANKING IN INDIA)

ब्रिटिश शासन काल से ही आधुनिक बैंकिंग का विकास माना जाता है। अतः भारतीय बैंकिंग की संरचना एवं संगठन का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—

(I) स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय बैंकिंग की संरचना,

(II) स्वतन्त्रता के बाद भारतीय बैंकिंग की संरचना,

(III) भारतीय बैंकिंग की वर्तमान संरचना स्थिति।

(I) स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय बैंकिंग की संरचना
(STRUCTURE OF INDIAN BANKING SYSTEM IN PRE-INDEPENDENCE)

1. अभिकर्ता गृहों की स्थापना (Establishment of Agency Houses)—भारत की देशी बैंकिंग प्रणाली ईस्ट इण्डिया कम्पनी के काल में समाप्त होने लगी थी क्योंकि देशी बैंक विदेशी बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे और उनमें अंग्रेजी भाषा के ज्ञान का अभाव था। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय बैंकरों की सेवाओं का लाभ उठाने के स्थान पर **अभिकर्ता गृहों** (Agency Houses) की स्थापना कर उनसे अपनी बैंकिंग सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करने लगे। आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का इतिहास वास्तव में इन्हीं अभिकर्ता गृहों की स्थापना से आरम्भ होता है।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सन् 1813 में भारत के विदेशी व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो जाने से अभिकर्ता गृहों पर काफी कुठाराघात हुआ और 1832 तक उनका पतन हो गया।

2. प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना (Establishment of Presidency Banks)—भारत में आधुनिक बैंकिंग के विकास के दूसरे युग का आरम्भ **प्रेसीडेन्सी बैंकों** की स्थापना से होता है। सन् 1806 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आज्ञा-पत्र के अनुसार 'बैंक ऑफ कलकत्ता' नाम का पहला आधुनिक बैंक स्थापित किया गया। इसके पश्चात् सन् 1840 में 'बैंक ऑफ बम्बई' और सन् 1843 में 'बैंक ऑफ मद्रास' की स्थापना हुई। ये तीनों 'प्रेसीडेन्सी बैंक' ईस्ट इण्डिया कम्पनी की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा आन्तरिक व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध करने के लिए स्थापित किये गये थे। इन्हें नोट निर्गमन का अधिकार भी दिया गया था। इस अधिकार को सन् 1862 में छीन लिया गया। कठिनाइयाँ होते हुए भी ये तीनों बैंक सन् 1920 तक सफलतापूर्वक चालू रहे। सन् 1921 में इन तीनों को मिलाकर **'इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया'** स्थापित किया गया।

3. सीमित दायित्व वाले संयुक्त बैंकों की स्थापना (Establishment of Joint Stock Banks of Limited Liability)—आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के तीसरे युग का प्रारम्भ 1860 से होता है जबकि संयुक्त पूँजी वाले बैंकों के साथ सीमित दायित्व के सिद्धान्त की शुरुआत की गई। इस वर्ष यूरोपीय प्रबन्ध के अन्तर्गत अनेक बैंकों की स्थापना हुई और सन् 1874 तक सीमित उत्तरदायित्व वाले बैंकों की संख्या 14 तक पहुँच गई। भारतीय प्रबन्ध के अन्तर्गत संचालित सबसे पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था जो सन् 1881 में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात् और भी कई बैंक स्थापित हुए जिनमें पंजाब नेशनल बैंक (1894) भी सम्मिलित है। सन् 1905 के स्वदेशी आन्दोलन ने तो इस प्रवृत्ति को और भी प्रोत्साहन दिया। सन् 1905 और 1913 के बीच स्थापित होने वाले बड़े-बड़े बैंक निम्न थे—

(i) बैंक ऑफ इण्डिया, (ii) पंजाब नेशनल बैंक, (iii) सेण्ट्रल बैंक, (iv) बैंक ऑफ बड़ौदा, (v) इलाहाबाद बैंक, (vi) दी इण्डियन बैंक, (vii) बैंक ऑफ मैसूर। इसके अतिरिक्त इस काल में बहुत छोटे-छोटे बैंक भी खोले गये जिनकी संख्या 1913 में 500 तक पहुँच गई थी।

(I) स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय बैंकिंग की संरचना

1. अभिकर्ता गृहों की स्थापना,
2. प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना,
3. सीमित दायित्व वाले संयुक्त बैंकों की स्थापना,
4. सन् 1913-17 का बैंकिंग संकट,
5. इम्पीरियल बैंक और रिजर्व बैंक की स्थापना।

4. **सन् 1913-17 का बैंकिंग संकट** (Banking Crisis of 1913-18)—सन् 1913 के पश्चात् ही देश में बैंकिंग का विकास इतनी तीव्रता के साथ हुआ था कि उसमें किसी प्रकार का स्थायित्व न आ सका था। भारतीय मुद्रा बाजार की अस्थायी प्रकृति के कारण बैंकिंग संकट के लिए उपयुक्त दशाएँ विद्यमान थीं। सन् 1912-13 में ही संकट के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे थे। शीघ्रतापूर्वक स्थापित होने वाले बैंक युद्ध-कालीन परिस्थितियों का आघात न सह सके।

युद्धकालीन अनिश्चितता के कारण लोगों का बैंकों के प्रति विश्वास घट रहा था और निक्षेप को निकालने की माँग बढ़ रही थी। सबसे पहले **'पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया'** पर संकट आया और सितम्बर सन् 1913 में वह दिवालिया हो गया। इसका सारी बैंकिंग प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ा और धीरे-धीरे एक-एक करके बहुत से बैंक दिवालिया होने लगे। सन् 1917-18 तक बैंकों के डूबने का क्रम बराबर चलता रहा। इस काल में 87 बैंक, जिनकी सामूहिक परिदत्त पूँजी और निक्षेप 175 लाख रुपये थी, डूब गये। यह पूँजी इस समय की कुल बैंकों की पूँजी का 50 प्रतिशत थी।

5. **इम्पीरियल बैंक और रिजर्व बैंक की स्थापना** (Establishment of Imperial Bank and Reserve Bank)—आधुनिक बैंकिंग के विकास में एक महत्वपूर्ण बात कम्पनी की शेयर पूँजी में सहभागिता सहित बंगाल (1840), बम्बई (1840), मद्रास (1843) के प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना थी जिन्हें 1921 में मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का निर्माण किया गया। इसकी परिदत्त पूँजी और रिजर्व उस समय 9.7 करोड़ रुपये थे और इसके निक्षेपों की कुल राशि 75 करोड़ रुपये थी। जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना नहीं हुई थी, इम्पीरियल बैंक सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता था।

1930 तक बैंकिंग पर यूरोपवासियों का प्रभुत्व जम गया था और भारतीय व्यापारियों की यह आम शिकायत थी कि ये बैंक उनके विरुद्ध भेद-भाव करते हैं। इस समस्या तथा भारतीय बैंकिंग प्रणाली की संरचना, कार्य पद्धति तथा पर्याप्तता से सम्बन्धित अनेक समस्याओं पर **विभिन्न प्रादेशिक बैंकिंग जाँच समितियों** (1930-31) ने विचार किया। उनके निष्कर्षों की केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति द्वारा समीक्षा की गई। इस समिति ने व्यापारिक बैंकों की कार्य-प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए भारतीय कम्पनी एक्ट, 1936 में आवश्यक संशोधन किये गये।

एक लम्बे समय से देश में एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और इस सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक सुझाव भी दिये जाते रहे। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति (1931) ने एक केन्द्रीय बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना एक **''निजी शेयरधारियों''** के बैंक के रूप में हुई परन्तु इस बैंक को सरकार के कड़े नियन्त्रण में रखा गया। **केन्द्रीय बैंक** को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये—(i) नोट निर्गमन का एकाधिकार सौंपा गया। (ii) इसे सरकार और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य दिया गया। (iii) यह उधार के नियन्त्रण, सार्वजनिक ऋण के प्रबन्ध, विदेशी मुद्रा रिजर्व के प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार था। (iv) रुपये की विनिमय दर का प्रबन्ध करने की वैधानिक जिम्मेदारी इसी बैंक को सौंपी गयी। (v) रिजर्व बैंक को ही सस्ती और तीव्र प्रेषण सुविधाएँ प्रदान करनी थीं और इससे यह भी अपेक्षित था कि यह कृषि ऋण की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान देगा।

रिजर्व बैंक की स्थापना के साथ भारतीय बैंक व्यवस्था वयस्क हो गई थी परन्तु इसमें अब भी कई महत्वपूर्ण दोष थे, जैसे—(i) अत्यधिक नगरीय उन्मुखता, (ii) कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा, (iii) अपर्याप्त क्षेत्र, (iv) यूरोपीय विनिमय बैंकों का विदेशी मुद्रा व्यवसाय पर प्रभुत्व, (v) दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्थाओं का अभाव।

इन कमियों के बावजूद भी भारतीय बैंक व्यवस्था निश्चित रूप से सुदृढ़ हो रही थी, वस्तुतः **औपनिवेशिक संसार में यह सबसे अधिक विकसित संस्थाओं में से एक थी।** इस प्रकार बैंकिंग

प्रणाली जो स्वयं भी भारत में बाजार अर्थव्यवस्था के विकास का परिणाम थी, ने इसके आगे के विकास को और अधिक बल प्रदान किया।

(II) स्वतन्त्रता के बाद भारतीय बैंकिंग की संरचना
(STRUCTURE OF INDIAN BANKING IN POST-INDEPENDENCE)

स्वतन्त्रता के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अनेक संरचनात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। देश में नियोजित विकास के सन्दर्भ में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किये ताकि देश के आर्थिक विकास में बैंकिंग संस्थाएँ अधिकाधिक योगदान प्रदान कर सकें। इस सन्दर्भ में किये गये उपायों का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत कर सकते हैं—

(II) स्वतन्त्रता के बाद भारतीय बैंकिंग की संरचना

1. रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण,
2. बैंकिंग नियम अधिनियम, 1949,
3. विकास बैंकों की स्थापना,
4. सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग विकास,
5. बैंकों का एकीकरण,
6. सहकारी बैंकों का समावेश,
7. आंचलिक ग्रामीण बैंक,
8. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना,
9. निर्यात-आयात बैंक की स्थापना।

1. **रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण** (Nationalisation of Reserve Bank)—1 जनवरी, 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ताकि रिजर्व बैंक देश के आर्थिक विकास में अधिकाधिक योगदान कर सके।

2. **बैंकिंग नियम अधिनियम**, 1949 (Banking regulation Act, 1949)—स्वतन्त्रता से पूर्व देश में कोई बैंकिंग विधान नहीं था फलतः बैंकिंग व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गये। अतः इन दोषों को दूर करने हेतु **भारतीय बैंकिंग (नियमन) अधिनियम, 1949** पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को बैंकिंग संस्थाओं के नियमन एवं नियन्त्रण हेतु विस्तृत अधिकार प्रदान किये गये।

3. **विकास बैंकों की स्थापना** (Establishment of Development Banks)— औद्योगिक वित्त सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेक विकास बैंकों (Development Banks) की स्थापना की गई। इन्हें सावधि ऋणदात्री संस्थाएँ (Term landing Institution) भी कहा जाता है। ऐसी कुछ प्रमुख संस्थाएँ; जैसे—(i) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India), (ii) भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम (The Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.), (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Banks of India), (iv) राज्य वित्त निगम (State Financial Corporation) आदि हैं। इन विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घकालीन अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

4. **सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग विकास** (Banking Development in Public Sector)—(i) अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति (All India Rural Credit Survey Committee) के प्रतिवेदन (1954) में प्रस्तुत सुझावों के आधार पर इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की स्थापना 1 जुलाई, 1955 में की गई।

(ii) सन् 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (सहायक) अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत भूतपूर्व विदेशी रियासती 8 बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक (Subsidiaries Bank) बना दिये गये। सन् 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं स्टेट बैंक ऑफ जयपुर का एकीकरण करके 'स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर' की स्थापना की गई। अतः अब स्टेट बैंक की सहायक बैंकों की कुल संख्या 7 है।

5. **बैंकों का एकीकरण** (Amalgamation of Banks)—स्वतन्त्रता के पूर्व अनेक छोटे-छोटे बैंक कार्यरत थे जो आपस में अस्वस्थ प्रतियोगिता करते थे जो कि देश में बैंकिंग विकास के

प्रतिकूल था। अत: 1950 से देश में बैंकों का विलीनीकरण प्रारम्भ हुआ। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में बैंकिंग कारपोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, हुगली बैंक, दी बंगाल सेन्टर बैंक का 1950 में विलीनीकरण करके एक नये बैंक **दी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई।** इसी प्रकार अन्य बैंकों का विलीनीकरण किया गया परन्तु इस कार्यक्रम की गति बहुत धीमी थी। अत: 1969 में रिजर्व बैंक को विलीनीकरण की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया।

6. **सहकारी बैंकों का समावेश** (Incorporation of Co-operative Banks)—भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सहकारी बैंकों का समावेश सन् 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इस प्रकार त्रिस्तरीय सहकारी बैंकिंग संरचना तथा द्विस्तरीय दीर्घकालीन साख व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि विकास बैंक स्थापित किये गये।

7. **आंचलिक ग्रामीण बैंक** (Regional Rural Bank)—भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक नया मोड़ सन् 1975 में दिखाई दिया जब सुदूर आंचलिक क्षेत्रों में साख सुविधाएँ पहुँचाने के व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण परिवेश में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों की साख आवश्यकताएँ पूरी करने हेतु स्थापित किये गये।

8. **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना** (Establishment of NABARD)—भारतीय अर्थव्यवस्था में **कृषि एवं ग्रामीण विकास के महत्व को** देखते हुए सन् 1982 में **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक** के रूप में (नाबार्ड) स्थापित की गई। इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु साख का नियमन करना तथा शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से ग्रामीण विकास के लक्ष्य प्राप्त करना है। यह संस्था ग्रामीण साख प्रदान करने वाली संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधा भी प्रदान करता है।

9. **निर्यात-आयात बैंक की स्थापना** (Establishment of EXIM Bank)—इसी प्रकार निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु तथा एक ही छत के नीचे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु सब सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 1982 में निर्यात-आयात बैंक की स्थापना की गई।

(III) भारतीय बैंकिंग की संरचना की वर्तमान स्थिति
(PRESENT BANKING STRUCTURE OF INDIA)

पिछले पृष्ठों में बैंकिंग संरचना के संक्षिप्त इतिहास के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि **भारतीय बैंकिंग** प्रणाली में देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ परिवर्तन भी होता रहा है। जहाँ **देशी बैंकिंग** प्रणाली से देश में बैंकिंग कार्य का प्रादुर्भाव हुआ, वहीं आज उच्च तकनीक युक्त **अन्तर्राष्ट्रीय स्तर** की बैंकिंग प्रणाली स्थापित हो चुकी है। आज बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत हाइटेक (High-tech) बैंकिंग का विकास हो चुका है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप देश की बैंकिंग संरचना के कई रूप विकसित हुए हैं जिसे संक्षेप में नीचे 2 चार्टों द्वारा दर्शाया गया है—

चार्ट I

भारतीय बैंकिंग संरचना

(Indian Banking Structure)

I. **शीर्ष बैंकिंग संस्थाएँ**
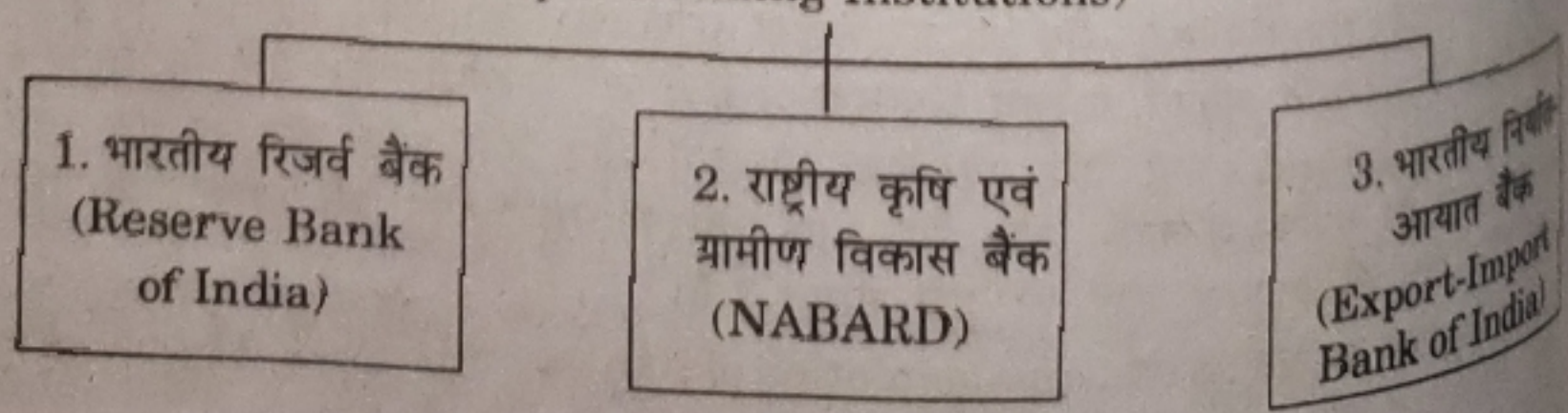
(Apex Banking Institutions)